

उर्वरकों की बढ़ती मांग
*172. श्री क. ल. सिंह माहान सिंह
मंगरोला

श्री ईश दत्त यादव : †

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश
में उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ रही है
और देश में उर्वरकों की उपलब्धता
कम हो रही है तथा मांग के अनुरूप
इनका उत्पादन बढ़ाने के प्रयास नहीं
किए गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उर्वरकों की
आपूर्ति उनकी मांग से कितनी कम है
और उनकी कुल मांग कितनी है तथा
सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान
उत्पादन क्षमता में कितना सुधार किया
है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में स्थापित किए
गए नए संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री
राम लखन सिंह यादव : (क) से
(ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर
रख दिया गया है।

†सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव
द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) से (ग) गत पांच वर्षों में
उर्वरकों के उपभोग, उत्पादन और आयात
के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :-

[न्यूट्रिएन्ट के रूप में (एन+पी+के)
कुल आंकड़े लाख टन में]

वर्ष	खपत	उत्पादन	आयात
1989-90	115.68	85.43	31.14
1990-91	125.46	90.44	27.58
1991-92	127.28	98.64	27.69
1992-93	121.55	97.36	29.76
1993-94 (अनंतिम)	128.33	90.47	31.67

सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाइट्रोजनी उर्वरक
(एन) अर्थात् यूरिया के उपयोग और
उत्पादन विगत पांच वर्षों में तेजी से
बढ़े हैं। फास्फेटिक उर्वरक (पी)
के मामले में गत दो वर्षों में उनके
उपभोग और उत्पादन अगस्त, 1992 में
उनके अनियंत्रण के कारण 1991-92
के स्तर से कम रहे हैं। देश में पोटाश
की संपूर्ण आवश्यकता आयातों के जरिये
पूरी की जाती है क्योंकि देश में इसके
वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार
नहीं हैं। विगत दो वर्षों में पोटाश की
खपत इसके अनियंत्रण के कारण 1991-
92 में खपत से कम रही है।

उर्वरकों की मांग और स्वदेशी
उपलब्धता के बीच अंतर को आयातों
के माध्यम से पूरा किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित
नये वृहद उर्वरक संयंत्रों ने उत्पादन
आरम्भ किया है :-

1991-92

(i) गुजरात नर्वेदा घाटी उर्वरक
कम्पनी लि० (जी०एन०एफ०सी०) भड़ौच
का अमोनियम नाइट्रोफास्फेट (23:23:0)
संयंत्र।

(ii) जी०एन०एफ०सी० भड़ौच का
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी ए
एन) संयंत्र

1992-93

(i) दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमि-
कल्स लि०, तलोजा (बम्बई के समीप)

का अमोनियम नाइट्रो फास्ट्रेट (23:23:0) संयंत्र।

(ii) नागाजुन फटिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, हाकीनाडा (आंध्र प्रदेश) का यूरिया संयंत्र।

1993-94

चम्बल फटिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०, गडपन (कोश के पास, राजस्थान) का यूरिया संयंत्र।

उपरोक्त सभी नये संयंत्रों को मिलाकर न्यूट्रियेंट्स की क्षमता में 7.77 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है (6.91 लाख टन नाइट्रोजन और 0.86 लाख टन फास्फेट)

श्री ईश दत्त यादव : माननीय सभा-पति जी, यह अच्छी बात है कि आज प्रश्नोत्तर काल में ऐसा प्रश्न आ गया जो देश के कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है और खाद से संबंधित है। खाद का कृषि उत्पादन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और सीमाध्य से माननीय प्रधान मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, वे इस को महसूस करते हैं और आंकड़े भी इन्होंने दिए हैं कि देश में कितना खाद का उत्पादन होता है और कितनी मांग है और कितना बाहर से खाद का आयात करना पड़ रहा है। लेकिन मान्यवर जो आंकड़े दिए गए हैं उन को देखने में यह लगता है कि वर्ष 1989 में 85.43 लाख टन का उत्पादन हुआ था खाद का देश में जो बढ़कर 90.44, फिर 96.64 और फिर 97.36 लाख हुआ लेकिन फिर 1993-94 में यह उत्पादन खाद का देश में घट गया। 1989 में जितना उत्पादन हुआ वह 1993 में आकर जट गया और इसी के अनुसार जो आयात होता है खाद का वह देश को अधिक करना पड़ा है। तो मैं आप के माध्यम से माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में खाद के उत्पादन में जो कमी हो रही है, इस का मूल कारण क्या है? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

दूसरा भाग यह है कि आप ने उत्तर में कहा है कि देश में पोटाश की संपूर्ण आवश्यकता आयातों के जरिए पूरी की जाती है क्योंकि देश में इस के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भंडार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सारी संभावनाएं इस प्रकार की समाप्त हो गई हैं कि वाणिज्यिक रूप से पोटाश का दोहन इस देश में संभव नहीं है?

श्री राम लखन सिंह यादव : श्रीमन, इस पोरियड में जब यहाँ खाद का उत्पादन कम हुआ, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो कुछ कारखाने बंद रह गए। कई जगह स्ट्राइक चल गई जिसके चलते उत्पादन कुछ कम हो गया है। लेकिन उस के बाद ही सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिस से कि जितना उत्पादन हो रहा है उस से उत्पादन कम न हो।

दूसरी चीज यह है कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर हमारे पुराने कारखाने बने हुए हैं। इसलिए भी उन की क्षमता कम हो रही है। हम यथासंभव उन की प्रगति करने और उन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इस में तीन तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पहला तो यह है कि इसमें शाट टर्न प्लानिक कर के कितनी कम से कम राशि लगाएं ताकि हमारी क्षमता बढ़े। दूसरे मीडियम साइज के हम कारखाने लगाएं ताकि कुछ वर्षों तक काम चले और तीसरा प्रयास हमारा यह है कि किस तरह से हम रिप्लेसमेंट करें या नई फैक्टरियां लगाएं। इन तीनों दिशाओं में हमारा कदम उठ रहा है। जैसी-जैसी आवश्यकता पड़ेगी वह हम कर रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारे देश में जितनी खपत है और जितनी उपज है उस के मूलाबिक हम नहीं कर सकते इसलिए कि किसान का डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जो बिलकुल बाजिब और सही है। आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। पहले किसान इतना जानता नहीं था। अब हर जगह लगाने के लिए उसे खाद चाहिए। इसलिए अपनी क्षमता बढ़ानी ही होगी। इस संबंध में जो घाटा होता है वह कम होता है। बाहर से मंगाकर पूति

करते हैं ताकि उनको किसी तरह से घाटा न हो। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से कारखाने खुल गये हैं। बाहर से हम मंगा ही रहे हैं। इससे क्षमता बढ़ी है। मिलजुल कर मैंने आप से कहा कि दस परसेंट हमारे अपने देश के अंदर खाद की उपज बढ़ जायेगी।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

श्री ईश दत्त यादव : मेरे पहले सप्लीमेंटरी का भाग दो जो था...

MR. CHAIRMAN: The Prime Minister wants to say something about your first supplementary.

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, I have explained in this Parliament several times that potassic fertilizers will continue to be imported for a long time because there is, at present, no possibility of our starting manufacture of potassic fertilizers on a large scale, leave alone the question of our becoming self-sufficient. We are making efforts. But, right now, for some time to come, it will not be possible to say that we will have any appreciable amount of manufacture of potassic fertilizers. This happens to be the case. But, we are having tie-ups with other countries so that we could have joint ventures there and the fertilizer could come straight here because they cannot sell all this fertilizer to any other country. The largest input of fertilizer is in India. Therefore they are also equally dependent on us. So, we are having all these tie-ups. But, locally, within the country, it is going to be one of the three or four commodities which will continue to be imported in the foreseeable future.

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न बिल्कुल साधारण है, उर्वरक मंत्री जी। आपने जो उत्तर दिया है कि गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित संयंत्रों ने उत्पादन आरम्भ किया है तो जो दो संयंत्र हैं आपका गुजरात नर्वेदा घाटी उर्वरक कम्पनी

का और दूसरा जी एन एफ सी, भड़ौच का, इससे कितना उत्पादन तीन वर्षों में हुआ है क्या आप बता सकते हैं?

श्री राम लखन सिंह यादव : इससे शक्ति बढ़ी है। एक्जेक्ट कितनी शक्ति बढ़ी है यह बताने के लिए मुझे नोटिस चाहिये।

श्रीमती भीणा वर्मा : उर्वरक क्षेत्र में नये अनुसंधान बराबर चलते रहते हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ जो हमारी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि प्राकृतिक साधनों से एक नये उर्वरक की आस्ट्रेलिया ने रिसर्च की। उसमें गाय के सींग में गोबर भर कर 6 महीने मिटटी में दबा कर रख दिया और उसमें पानी मिलाकर एक नये उर्वरक का अनुसंधान किया गया। क्या सरकार को इस अनुसंधान के बारे में जानकारी है? यदि है तो कितनी है और यदि नहीं है इसके बारे में आस्ट्रेलिया से या हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें। मेरे प्रश्न का भाग दो यह है कि सरकारी क्षेत्र में जो उर्वरक का उत्पादन हो रहा है इनके निजीकरण के बारे में क्या सरकार सोच रही है? यदि हां तो इसका भी जवाब दें?

श्री राम लखन सिंह यादव : अभी जो माननीया सदस्या ने इन्फरमेशन दी है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का हवाला दिया है तो मुख्य मंत्री से तो जानकारी लेने में देर लग सकती है लेकिन यहाँ खुद आपने उनसे बात की हुई है इसलिए इस योजना के बारे में आप से बात कर लूंगा। मैं व्यक्ति रूप से सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं खुद गाय रखता हूँ। अगर उसके सींग में गोबर भर कर काम चलता है और खाद बनती है तो हमारे लिए नफा होगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस चीज को पसन्द करता हूँ। इस टेक्नोलॉजी की अभी हम को जानकारी नहीं है। माननीया सदस्या से बात करके मैं लाभ उठाऊंगा।

श्रीमती बीणा वर्मा : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से यदि आप स्वयं बात करें और इस संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से..

श्रीमती बीणा वर्मा : मैंने निजीकरण के बारे में पूछा था।

श्री राम लखन सिंह यादव : अभी निजीकरण की दिशा में कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में खाद के सिलसिले में मांग और उत्पादन का अनुपात क्या रहा है मध्य प्रदेश में फर्टिलाइजर की कितनी मांग रही? क्या यह सही है कि उत्पादन की अपेक्षा मांग अधिक रही और यदि यह सही है तो इस अनुपात को कम करने के लिये केंद्र सरकार की तरफ से क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या सरकार को ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि फर्टिलाइजर का उपयोग जो हमारे किसान भाई करते हैं, उसमें उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और खेतों की उर्वरक शक्ति भी कम हुई है? यदि यह सही है और इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो एन.एफ.एल. है, क्या यहाँ की कार्य-प्रणाली के बारे में आपको कोई शिकायतें वहाँ की डिफरेंट यूनिट्स के माध्यम से मिली हैं? यदि मिली हैं तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम लखन सिंह यादव : जहाँ तक मध्य प्रदेश में डिमांड और सप्लाई का प्रश्न है, मेरा प्रयास यही है कि जहाँ से जितनी किसानों की डिमांड के लिये

वहाँ की गवर्नमेंट या और कोई मेंबर भेजता है, उस पर इन्क्वायरी कराकर यथासंभव उसको अधिक करते हैं लेकिन कम नहीं होने देते हैं। इसमें कुछ देर हो सकती है लेकिन उसको अवश्य करते हैं। अभी हाल में दो प्रदेशों से डिमांड आयी थी। हमने उनको तीन दिनों के अंदर, जितनी डिमांड बिहार से थी और जितनी डिमांड महाराष्ट्र से थी, उनको भेज दी है। मध्य प्रदेश की कितनी डिमांड है और कितना हम हर साल उनको देते हैं, अभी इसके आंकड़े मैं नहीं दे सकता हूँ।

जहाँ तक—क्या प्रश्न था आपका?

श्री मोहिंदर सिंह कल्याण : एन. एफ. एल. की शिकायतें।

श्री राम लखन सिंह यादव : शिकायतों के संबंध में मुझे यह कहना है कि कुछ न कुछ शिकायतें आया ही करती हैं। जो भी हम से बन सकता है, जो वाजिव है उस पर इन्क्वायरी करते हैं और जब एक्शन लेने की बात होती है तो वह भी करते हैं। वहाँ से कौन सी शिकायत है अगर इस बारे में माननीय सदस्य को मालूम हो तो वह चिट्ठी अभी भी दे सकते हैं ताकि मैं उसको देख सकूँ।

SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: The reply circulated talks about the gap between production and consumption. As far as potash is concerned, one can understand it because of the non-availability of potash. You can do nothing except import. But as far as the other fertilisers are concerned, I would like to know: what is the installed capacity and what is the percentage of capacity utilisation?

श्री राम लखन सिंह यादव : इस संबंध में तो अभी प्रधान मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। हमारे यहाँ रा-मेटोरियल उपलब्ध नहीं है और अभी कुछ दिनों तक होने की संभावना है। बाद में कोई खान निकल तो अलग बात है। वैसे जितनी डिमांड है हमें जितनी आवश्यकता पड़ती है, उतना हम उसको इम्पोर्ट करते रहेंगे। जहाँ

तक बाकी खाद का सवाल है कि क्या हम अपने यहां बना सकते हैं तो मैंने जवाब दिया है कि हर जगह हम इसको बढ़ा रहे हैं और आगे और बढ़ाएंगे। नयी फैक्टरी भी लगाएंगे और हर साल 10 प्रतिशत पहले से अधिक उत्पाद त करने जा रहे हैं।

SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL: Mr. Chairman, Sir, I asked a very specific question. I asked about the installed capacity of the various fertiliser factories which can use the raw material available. I wanted to know about the gap between the installed capacity and the percentage of capacity utilisation wherever the availability of raw material is there. I am not asking about potash. I can understand about it. The hon. Prime Minister has mentioned about it. We have to import potash. But the important thing is that there has to be efficient utilisation of the capacity already established.

SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV: Sir, I would require a separate notice for this question.

श्री राम गोपाल यादव : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जो जवाब दिया है उसमें कंजम्पशन किनने वर्षों में कितना रहा है, यह बताया है। सैण्ड क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, खेती योग्य जमीन भी बढ़ रही है। इसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। मेरा बहुत टेक्नीकल सवाल है। सवाल यह है कि जो कंजम्पेशन बढ़ रहा है वह प्रति हेक्टेयर बढ़ रहा है या जो खेती योग्य जमीन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से बढ़ रहा है। अगर प्रति हेक्टेयर बढ़ रहा है तो पिछले पांच सालों में फर्टिलाइजर का कंजम्पशन प्रति हेक्टेयर क्या था, यह बताने की कृपा करें?

श्री राम लखन सिंह यादव : सब से ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि वह पहले इसकी उपयोगिता नहीं जानते थे। अब बढ़ने का मूल कारण है कि हम किसान फर्टिलाइजर की उपयोगिता को समझने लगा है। जहां वह खाद

डालता नहीं था या नाम मात्र के लिए डालता था अब उसको हर जगह लगाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए उसकी डिमांड दिनोदिन बढ़ती जा रही है तथा अभी और भी बढ़ेगी। आप भी किसान हैं और हम भी किसान हैं और यह जानते हैं कि किसान की मनोवृत्ति क्या है।

श्री राम गोपाल यादव : मेरी जानकारी में कंजम्पशन प्रति हेक्टेयर कम हो रहा है। जमीन बढ़ रही है, इसलिए कंजम्पशन बढ़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में प्रति हेक्टेयर कितना कंजम्पशन रहा है? (व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव : पिछले पांच वर्षों में जाना रहा है, इसका सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। उसके लिए अलग से सूचना दीजिये, मैं आपका सूचना भिजवा दूंगा।

श्री राम गोपाल यादव : बाद में भिजवा दीजियेगा।

श्री राम लखन सिंह यादव : मेरे ख्याल से अभी इसमें प्रति हेक्टेयर तो है ही लेकिन सब से ज्यादा किसान की मनोवृत्ति में है क्योंकि वह अब इसकी उपयोगिता समझने लगा है। दिककत हमारी वहां बढ़ जाती है जब हम केवल परिया का इस्तेमाल उपज बढ़ाने के लिए करते हैं तो हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति दिनोदिन घटती जा रही है। हमने खुद देखा है कि इस साल जो उपज हुई केवल परिया लगाने से अगले साल वह उपज घट जाती है नतीजा यह होगा कि जमीन बिल्कुल ऊसर हो जाएगी। इसलिए और खाद दे कर सप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसमें जो हमारे घरों में गोबर की खाद बनती है, वह सब से उपयोगी है। इसलिए सब को मिला कर इस प्रश्न को देखना होगा और हल करना होगा।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, it is seen from the statement that in 1992-93 the consumption was 121 lakh tonnes, and it has gone up to 128 lakh tonnes in 1993-94. At the same time,

the production has come down from 97.36 lakh tonnes to 90.47 lakh tonnes. Once the consumption has gone up and the production has come down, we are depending more on its import. May I know from the hon. Minister what steps he has taken or he is going to take to increase the domestic production to meet the requirement as much as possible and to avoid the import?

श्री राम लखन सिंह यादव : मैंने इस प्रश्न के बारे में आंशिक रूप में पहले जवाब दे दिया है। कई कारणों से कमी हो गई है लेकिन इमको बढ़ाने के लिए मारे उपाय हम लोग कर रहे हैं। क्पेसिटी बढ़ा रहे हैं। दर्या टेक्नोलोजी की जहां आवश्यकता है, वह भी जितनी चाहिये उतनी तो नहीं लेकिन कुछ बढ़ा रहे हैं। उत्पादन घटेगा तो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन पूरे देश में कितना और लगेगा अभी मैंने कहा कि पूरे देश में कुल 10 प्रतिशत इस साल पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बढ़ती हुई मांग जो केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती, क्या बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है?

श्री राम लखन सिंह यादव : भारत सरकार का प्रयास है कि जिस तरह से फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़े जाहे जिस स्रोत से आए लेकिन उत्पादन बढ़ना चाहिये ताकि किसान को फायदा हो। (व्यवधान)

श्री जगजाल सिंह : चार कारखाने बंद हैं, उनके बारे में मंत्री जी ने क्या सोचा है, कब तक शुरू होंगे? यह है तोरखपुर, सिंदरी, दुर्गापुर और हल्दिया (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI : As a Member of the Committee on Public Undertaking, I compliment the Prime Minister for the financial restructuring that has been done. That was most

liberal in recent times. Finance is the biggest problem of the public sector undertakings. I would like to know whether the Government will allow sale of the surplus land of the public sector, which is the prime land in most of the metropolitan cities so that they can have resources and the problem that they are facing can be solved. I would like the Prime Minister to react to it. ... (Interruptions)

SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV : This is a matter which concerns the principle we have at heart. We will have to take a decision whether the surplus land should be sold or not.

MR. CHAIRMAN : The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विमान सेवा कम्पनियों के लिए दिशा-निर्देश

* 162. श्री दिग्विजय सिंह :

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या नामर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व गैर-सरकारी विमान सेवा कम्पनियों के लिये उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विमान सेवाओं के संबंध में कोई सेवा शर्तें/नियमावली/निति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं अथवा ये कम्पनियां अपने ही नियमों का पालन करती हैं;

(ख) यदि सरकार ने कोई नियमावली/सेवा शर्तें/निति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं तो उनका ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी विमान सेवा कंपनियों की समय-सारणी और उनके द्वारा लिये जाने वाले किराये को सरकार की सहमति प्राप्त है;